सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड

राज्य की चतुर्थ विधान सभा के वर्ष, 2019

के प्रथम सत्र में

श्रीमती बेबी रानी मौर्य

माननीय राज्यपाल, उत्तराखण्ड

का

अभिभाषण

देहरादून, सोमवार, 11 फरवरी, 2019 (माघ 22, शक सम्वत्, 1940)

उत्तराखण्ड राज्य के माननीय विधान सभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष एवं विधान सभा के माननीय सदस्यगण;

मैं आप सभी महानुभावों का वर्ष, 2019 में विधान सभा के प्रथम सत्र में हार्दिक स्वागत करती हूँ और देव भूमि उत्तराखण्ड को एक आदर्श राज्य के रूप में विकसित करने में दिये जा रहे सहयोग के लिए आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। आप के माध्यम से मैं प्रदेश की उत्तरोत्तर वृद्धि की भी कामना करती हूँ। मुझे आशा है कि हम आगामी वर्ष में विकास की नई ऊँचाईयों को प्राप्त करेगें, ताकि प्रत्येक क्षेत्र में हम नया आयाम स्थापित कर सकें।

(1) मेरी सरकार द्वारा जनसामान्य की सुविधा हेतु वेबसाइट (eregistration.uk.gov.in) पर विभिन्न प्रकार की सुविधाये यथा ई–सर्च, ऑनलाइन कैलकुलेशन आफ स्टाम्प ड्यूटी, पब्लिक डाटा एन्ट्री, रजिस्ट्री कराने के लिये ऑनलाइन समय आबंटन तथा ऑनलाइन विवाह पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

- जनपद हरिद्वार के उप निबन्धक कार्यालय लक्सर में विभागीय भवन निर्माण कराये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।
- रूपये पच्चीस लाख मूल्य तक की स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में अनुमन्य 25 प्रतिशत तक की छूट किसी भी महिला क्रेता को उसके जीवन काल में अधिकतम दो बार अनुमन्य की गयी है।
- राज्य के समस्त जिलों की सीमाओं को यथावत रखते हुए जिलों में अवस्थित समस्त उपजिलों का क्षेत्राधिकार समवर्ती किये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है।
- जन सामान्य की सुविधा के लिये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एवं रिन्यूवल की व्यवस्था ऑन–लाइन की जा रही है।

- राज्य के समस्त कार्मिकों के लिये मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एच.आर. एम.एस.) की व्यवस्था कर उनकी सर्विस–बुक, वेतन पर्ची तथा अन्य अभिलेख ऑनलाइन किये जा रहे हैं।

- कोषागारों के माध्यम से किये जाने वाले समस्त लेन–देन ऑनलाइन कर प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए राज्य में ई–स्टाम्प योजना लागू की गयी है।

- पेंशनरों के वार्षिक सत्यापन की पुरानी व्यवस्था को सरल करते हुए, जिस माह पेंशनर सेवानिवृत्त हुआ है उस माह में तथा पारिवारिक पेंशनरों की स्थिति में पेंशनर की मृत्यु के माह में वार्षिक सत्यापन की नवीन सुविधाजनक व्यवस्था लागू की गयी है।

- कोषागार पोर्टल की सहायता से समस्त आहरण–वितरण अधिकारी/ विभागाध्यक्ष/शासन के प्रशासनिक विभागों द्वारा अपने विभाग से संबंधित सूचनायें प्राप्त करने एवं समस्त कार्मिकों तथा पेंशनरों द्वारा अपने से संबंधित सूचनायें डाउनलोड किये जाने की व्यवस्था तैयार की गयी है।

- राज्य के समस्त जनपदों में सोसाइटियों का पंजीकरण/मॉडिफिकेशन /नवीनीकरण के कार्यों को ऑनलाइन किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है। यूजर आई0डी0 के माध्यम से लॉगइन करके निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा किये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है।

- विगत वित्तीय वर्ष के सापेक्ष चार हजार छः सौ दो करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो कि गत वर्ष के सापेक्ष 19 प्रतिशत अधिक हैं।

- जी०एस०टी० की परिधि से बाहर रखे गये वस्तुओं पेट्रोल, डीजल, ए०टी०एफ० एवं नैचुरल गैस तथा मदिरा उत्पादों पर एक हजार दो सौ बारह करोड रूपये का राजस्व अर्जित किया गया है।

- जी0एस0टी0 मित्र योजना के माध्यम से न केवल दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित छोटे करदाताओं को सहायता प्रदान की गयी वरन् शिक्षित युवाओं हेतु रोजगार भी सृजित किया गया है। द्वितीय चरण हेतु 470 अभ्यर्थी अर्ह पाये गये हैं, जिन्हें प्रशिक्षित किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।
- राज्य सरकार द्वारा जनहित में पेट्रोल व डीजल पर वैट की दर को तर्कसंगत बनाते हुए पेट्रोल एवं डीजल की दरों में कमी की गयी है।
- व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना लागू की गयी है, पंजीकृत व्यापारियों की मृत्यु की दशा में मृतक आश्रित को तात्कालिक आर्थिक सहायता के रूप में रूपये पाँच लाख भुगतान करने की व्यवस्था की गयी है।
- जी०एस०टी के प्राविधानों तथा विशिष्ट रूप से ई–वे बिल जनरेट करने में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण हेतु राज्य कर, मुख्यालय में हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। इसके साथ ही हरिद्वार तथा रूद्रपुर कार्यालय में 24X7 हेल्पडेस्क सेवा स्थापित की गई है।
- टैक्स पेयर फ्रैंडली उपाय के रूप में जीएसटी के अधीन राज्य हेतु पंजीयन की मौद्रिक सीमा ₹ 10 लाख वार्षिक से बढ़ाकर ₹ 20 लाख वार्षिक किए जाने सम्बन्धी उपबंध किया गया है।
- स्थानीय उत्पादों यथा रिंगाल, रामबान पर आधारित उत्पादों पर कर की दर 18 प्रतिशत से कम करते हुए 5 प्रतिशत की गयी है।
- ''गुड़'' को कर मुक्त श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- समाधान योजना अपनाए जाने के लिए कुल आवर्त की सीमा पचास लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रूपये कर दी गयी है।

(2) राज्य के नियोजित विकास हेतु विजन 2030 तैयार किया गया है।

- विभागीय कार्यो की समीक्षा हेतु विभागों से वित्तीय एवं भौतिक आंकड़ों को प्राप्त की जाने वाली सूचनाओं को पेपर लैस करने एवं नियमित अनुश्रवण एवं समीक्षा हेतु "ई–आकलन" (ऑनलाइन) पोर्टल तैयार किया गया है।

- राज्य के सतत् विकास हेतु नियोजन तथा नीति निर्धारण को प्रभावी, उपयोगी तथा व्यवहारिक बनाये जाने हेतु "उत्तराखण्ड स्टेट सेन्टर फॉर पब्लिक पॉलिसी एण्ड गुड गवर्नेन्स" का गठन किया गया है।

(3) उत्तराखण्ड राज्य के आर्थिक विकास में उद्योग क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। **राज्य** गठन के पश्चात् देश के उच्च विकास दर पाने वाले शीर्षस्थ राज्यों में उत्तराखण्ड राज्य सम्मिलित है।

- निवेश को बढ़ावा देते हुए राज्य का पहला "निवेशक सम्मेलन–डेस्टिनेशन उत्तराखण्ड" माह अक्टूबर, में देहरादून में आयोजित किया गया, जिसका शुभारम्भ मा0 प्रधानमंत्री द्वारा किया गया।

- राज्य के कुछ बेहतरीन व प्रमुख उद्योगों की प्रदर्शनी "थीम मण्डप", "इमर्सिव उत्तराखण्ड" कार्यक्रम में उद्योग जगत से जुड़े हुए 4000 से अधिक प्रतिनिधियों, निवेशकों, देश व विदेश के उद्योगपतियों, डेलीगेट्स, उद्यमियों और अकादमिक आगन्तुकों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

- निवेश क्षेत्रों में एक सौ चौबीस लाख करोड़ रूपये के कुल 601 एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर किये गये हैं। निर्धारित 80 कार्य बिन्दुओं पर सजगता से कार्यवाही की जा रही है।

- राज्य में निवेश को सुगम बनाने हेतु "उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन व्यवस्था" ऑनलाइन रूप से लागू कर दी गई है। इस व्यवस्था के तहत दो हजार पॉच सौ चौवन निवेश के प्रस्ताव ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं,

जिससे नौ हजार छः सौ सत्तासी करोड़ रूपये के पूंजी विनियोजन के साथ ही अड़तीस हजार लोगों को रोजगार दिया जाना प्रस्तावित है।

- ''ईज आफ डूइंग बिजनेस'' की भावना के अनुरूप ''जमींदारी उन्मूलन एवं विनाश अधिनियम'' में संशोधन कर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए भूमि क्रय करने हेतु जिलाधिकारी को अधिकारों का प्रतिनिधायन किया गया है।
- पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक प्रयोजन के लिए भूमि क्रय करने हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन पर स्वतः ही भू–उपयोग परिवर्तन का प्राविधान किया गया है।
- एमएसएमई क्षेत्र में दो हजार उन्नासी इकाइयों की स्थापना के माध्यम से रूपये चार सौ बारह करोड़ का पूंजी विनियोजन तथा दस हजार सात सौ सैंतीस लोगों को रोजगार दिया गया है।
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिये अप्रैल, 2017 से 5 वर्षों के लिये ''औद्योगिक विकास योजना'' लागू की गई है, जिसमें पूंजी निवेश उपादान पर 30 प्रतिशत, अधिकतम रूपये पॉच करोड़ तक का उपादान एवं 5 वर्ष तक प्लाण्ट एवं मशीनरी पर बीमा प्रीमियम की शत्–प्रतिशत बेरोजगार युवकों हेतु को रोजगार के अवसर बढ़ाये जाने के दृष्टिगत प्रतिपूर्ति का प्राविधान किया है।
- केन्द्रीय प्लास्टिक और इंजीनियरिंग प्रौद्योगिक संस्थान कौशल विकास केन्द्र भवन का शिलान्यास आईटीआई, विकास खण्ड डोईवाला में किया गया है।
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों द्वारा 909 परियोजनाओं के सोलह करोड़ रुपये के मार्जिन मनी के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं तथा 1109 परियोजनाओं को रूपये इक्कीस करोड़ की मार्जिन मनी संवितरित की गई है।
- प्रदेश के हस्तशिल्प व हथकरघा संबंधित उत्कृष्ट उत्पादों को ''हिमाद्रि'' ब्राण्ड नेम के साथ विपणन किया जा रहा है।

- मिडिल ईस्ट के निवेशकों से सम्पर्क स्थापित करने के उद्देश्य से सम्पन्न एन्यूअल इन्वेस्टमेंट मीटिंग 2018 में प्रतिभाग कर राज्य में उपयुक्त औद्योगिक वातावरण के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण दिया गया है।

(4) मेरी सरकार भारत सरकार द्वारा संचालित डिजिटल इण्डिया लैण्ड रिकॉर्ड मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत चिन्हित पॉयलट जनपद अल्मोड़ा एवं पौड़ी गढ़वाल में भू–अभिलेखों के आधुनिकीकरण किये जाने की कार्यवाही कर रही है।

- "राजस्व प्रशासन आपके द्वार" नामक कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है जिसमें राजस्व अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित ग्राम प्रधानों, लेखपाल/राजस्व उपनिरीक्षक की उपस्थिति में शिविरों का आयोजन कर मृतक खातेदारों के वारिसान के नाम स्थल पर ही किये जाने एवं निर्विवादित विरासत दर्ज करने के मामलों का निस्तारण एवं भूमि सम्बन्धी अन्य प्रकरणों का नियमानुसार निस्तारण किया जा रहा है।

- पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबन्दी किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है। चकबन्दी कमेटी का गठन किया गया है। चकबन्दी हेतु प्रस्ताव तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

(5) भारतीय सेना एवं अर्द्धसैनिक बलों के शहीद सैनिकों के आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं में अनुकम्पा के आधार पर सेवायोजन का प्रावधान किया गया है।

- सम्मिलित राज्य सेवा के अधिकारियों हेतु सेवा पूर्व प्रशिक्षण के अतिरिक्त प्रादेशिक सिविल सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा के अधिकारियों हेतु सेवाकालीन तथा विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है।

- लोक सेवा आयोग के माध्यम से रिक्त पदों के सापेक्ष 103 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, 945 रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया गतिमान है।

- अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से कुल रिक्तियों के सापेक्ष 6486 पदों की विज्ञप्ति जारी कर दी गयी है तथा शेष पदों की चयन प्रक्रिया गतिमान है।

(6) मेरी सरकार द्वारा डैशबोर्ड–उत्कर्ष के माध्यम से राज्य परियोजनाओं के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की स्थापना करते हुए विभागों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

- दूरस्थ क्षेत्रों में संचार व्यवस्था एरोस्टेट (बैलून) के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु आई0टी0डी0ए0 एवं आई0टी0आई0 मुम्बई के मध्य समझौता करते हुए परियोजना का प्रथम चरण पूर्ण कर लिया गया है।
- भारत सरकार की संस्थाओं के साथ सूचना प्रौद्योगिकी भवन में राज्य ड्रोन पर शोध एवं प्रशिक्षण तथा साइबर सुरक्षा पर प्रशिक्षण हेतु नेशनल टेक्निकल रिसर्च आरगेनाइजेशन (NTRO) व नेशनल क्रिटिकल इन्फारमेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेन्टर (NCII PC) के साथ अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया है।
- नेशनल टेक्निकल रिसर्च आरगेनाइजेशन के तहत क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क (SWAN) के माध्यम से 133 स्वॉन केन्द्रों का बैण्ड विड्थ उच्चीकरण कर दिया गया है।
- राष्ट्रीय सूचना अवस्थापना की पायलट परियोजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में हरिद्वार जनपद में 220 ग्राम पचांयतो में तीन–तीन हॉरिजेन्टल कार्यालयों सहित कनेक्टिविटी के अन्तर्गत समस्त ग्राम पचांयतों में उपकरण स्थापित करने के पश्चात् चिन्हित ग्राम पचांयतो तथा हॉरिजेन्टल कार्यालयों को संयोजित कर दिया गया है।
- प्रदेश में ब्लॉक एवं तहसील स्तर पर विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।
- नागरिकों को सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु कॉमन एप्लीकेशन पोर्टल को तैयार करते हुए लगभग 100 सेवाएं प्रारम्भ करने का लक्ष्य रखा गया है।

- भारत सरकार द्वारा संयुक्त रुप से नव युग मोबाइल अनुप्रयोग (उमंग) एप के माध्यम से नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय ई–गवर्नेस क्षेत्र से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित किया गया है।
- डिजिटल माध्यम से नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत सात हजार तीन सौ देवभूमि जनसेवा केन्द्र कार्यशील किये जा चुके हैं। अद्यतन अस्सी हजार व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(7) मेरी सरकार ने मुख्यमंत्री समाधांन पोर्टल के अन्तर्गत स्मार्ट आई0वी0आर0 सिस्टम के माध्यम से सार्वजनिक शिकायत को मोबाइल दूरभाष पर प्राप्त कर उनका निस्तारण किये जाने हेतु टोल फ्री नं0 1905 सेवा का शुभारम्भ किया गया है, जिसमें प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है।

- सुशासन, कार्यो में पारदर्शिता, जन सामान्य को नियत समय में सेवाएं प्रदान करने हेतु उच्चकोटि की कार्य संस्कृति को अपनाये जाने विभिन्न स्तरों से प्राप्त शिकायतों के निवारण के दृष्टिगत राज्य में "उत्तराखण्ड लोक सेवा अभिकरण" का गठन किया गया है, जिसके अन्तर्गत सेवा का अधिकार आयोग एवं समाधान पोर्टल से सम्बन्धित कार्य संचालित किये जायेंगे।

(8) मेरी सरकार समाज की सहभागिता से विधि सम्मत व्यवस्था बनाये रखना, अपराध नियंत्रण, शान्ति व्यवस्था एवं कानून–व्यवस्था स्थापित करने, पर्यटकों की सुरक्षा तथा सुरक्षित पर्यावरण बनाये रखने के प्रति समर्पित है।

- राज्य महिला सहायता प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। अपराध से पीड़ित महिलाओं के अब तक प्राप्त 204 प्रकरणों में महिलाओं को चार करोड़ तैंतीस हजार रूपये की धनराशि क्षतिपूर्ति, प्रतिकर के रूप में भुगतान की गई है।
- उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कार्मिको को उत्कृष्ट सेवा सम्मान देकर 84 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है।

- भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना के अन्तर्गत वर्तमान में विभिन्न इमरजेंसी सेवाओं को एकीकृत कर सम्पूर्ण सेवाओं के लिए एक कॉमन इमरजेंसी नम्बर 112 में परिवर्तित कर सम्पूर्ण राज्य हेतु देहरादून में स्टेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेन्टर मुख्य कन्ट्रोल रुम की स्थापना की गयी है।
- होमगार्ड्स स्वयं सेवकों का मानदेय बढ़ाकर उनकी संख्या दस हजार किये जाने के लिये होमगार्ड्स की वृद्धि की जा रही है।
- कारागार में निरूद्ध बंदियों हेतु उचित रख–रखाव हेतु स्वच्छ जल, बिस्तर, सुख सुविधा एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा हैं।
- कारागारों में निरूद्ध बंदियों की शिक्षा हेतु एन0आई0ओ0एस0 द्वारा जिला कारागारों में विशेष अभियान चलाकर कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान की जा रही है। कौशल विकास कार्यक्रम के तहत विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण के साथ–साथ खेल–कूद के साधन उपलब्ध कराये जा रहे है।

(9) **आपदा की दृष्टि से उत्तराखण्ड एक संवेदनशील राज्य है। मेरी सरकार ने विभिन्न** प्रकार की आपदाओं के दृष्टिगत आपदा प्रबन्धन तंत्र को मजबूत तंत्र बनाये जाने तथा आपदाओं के न्यूनीकरण के उपाय के सम्बन्ध में योजना एवं नीति का निर्माण किये जाने हेतु शीर्ष संस्था के रूप में राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना की है।

- आई0आई0टी0 रूड़की के सहयोग से राज्य में भूकम्प पूर्व चेतावनी यंत्र की स्थापना की जा रही है।
- राज्य को सरकारी भवनों को भूकम्परोधी बनाने हेतु अभी तक पन्द्रह हजार भवनों का रैपिड विजुवल स्क्रीनिंग कराया जा चुका है।
- आपदा की स्थिति में त्वरित संचार व्यवस्था हेतु राज्य में 84 नये सैटेलाइट फोन क्रय किये गये है, जिनका जनपदवार वितरण कर दिया गया है।

- राज्य में विभिन्न स्थानों पर कुल 176 अर्ली वार्निंग सिस्टम/रेनगेज/स्नोगेज की स्थापना हेतु भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई0एम0डी0) के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित कर स्थापित किये जा रहे हैं।
- राज्य में उत्तराखण्ड रिवर मार्फोलॉजी इन्फारमेंशन सिस्टम का विकास किया गया है।
- राज्य का डिजास्टर रिस्क डाटाबेस तैयार किया गया है।
- राज्य के समस्त महिला एवं युवक मंगल दलों को खोज, बचाव एवं प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षित किये जाने हेतु कार्यवाही की गई है।
- राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की वेबसाइट हिंदीं/अंग्रेजी में विकसित की गयी है।

(10) मेरी सरकार ने सिचाई क्षेत्र में वृद्धि किये जाने के दृष्टिगत गोला नदी पर बहुप्रतीक्षित जमरानी बाँध बहुउद्देशीय परियोजना निर्माण हेतु लगभग सभी औपचारिकतायें पूर्ण कर ली गयी है। जमरानी बाँध परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही गतिमान है। योजना के निर्माण से 14 मेगावॉट विद्युत उत्पादन के साथ-साथ पर्यटन क्षेत्र का विकास भी होगा।

- "उत्तराखण्ड वाटर मैनेजमेन्ट प्रोजेक्ट" गठित कर बाह्य सहायतित योजना अन्तर्गत वित्त पोषण हेतु भारत सरकार को प्रेषित की गयी है। योजना प्रधानमंत्री के 2022 तक कृषकों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सहायक होगी।
- देहरादून एवं उपनगरीय क्षेत्रों की वर्ष 2051 तक अनुमानित आबादी में वृद्धि के दृष्टिगत पेयजल आपूर्ति के लिए सौंग नदी पर नौ सौ अठहत्तर करोड़ की लागत से सौंग पेयजल बाँध योजना बनायी जानी प्रस्तावित है। उक्त बाँध

निर्माण योजना रिसपना एवं बिन्दाल नदियों के पुनर्जीवीकरण में भी सहायक होगी। योजना का कार्य प्रारम्भ करने की प्रक्रिया गतिमान है।

- त्यूनी–प्लासू जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य इस वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है। परियोजना से 53 मेगावाट विद्युत के साथ–साथ सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी।

- हरिपुरा एवं तुमरिया जलाशय की खाली भूमि पर 40 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापना की योजना तैयार की गई है। योजना से लगभग 40 मेगावाट हरित ऊर्जा का उत्पादन होगा।

- सिंचाई सुविधाओं में आधुनिक एवं अभिनव तकनीकों का प्रयोग भी प्रारम्भ किया जा रहा है एवं पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के क्रम में नलकूप एवं लघुडाल निर्माण की योजनाओं में स्प्रिंकलर प्रणाली से सिंचाई किये जाने को प्राथमिकता दी जा रही है।

- वर्षा जल संग्रहण एवं भू–जल संवर्द्धन हेतु विभिन्न जलाशयों का निर्माण प्रारम्भ किया गया है तथा पर्वतीय जनपदों में वर्षा जल संग्रहण हेतु विभिन्न झीलों के निर्माण के लिए डी0पी0आर0 बनाने का कार्य द्रुत गति से किया जा रहा है।

- नैनीताल झील के पुनर्जीवीकरण हेतु कार्य योजना तैयार कर ली गयी है। कोसी, रिस्पना एवं बिंदाल नदियों को पुनर्जीवित करने हेतु सर्वेक्षण कर कार्य योजना बनाई जा रही है।

(11) सिंचाई योजना का विस्तार कर राज्य योजनान्तर्गत एवं केन्द्रपोषित योजनान्तर्गत कुल तेरह हजार इकतालीस लाख की धनराशि प्राप्त हुई है।

- नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर में 25 आर्टीजन कूपों में चार सौ तिरासी लाख का व्यय करते हुए 454 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है।
- हर खेत को पानी उपलब्ध कराने हेतु चौंतीस हजार नौ सौ उन्तालीस लाख की 422 क्लस्टर योजनाओं के प्रस्ताव वित्तीय स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं।

(12) मेरी सरकार द्वारा मद्यनिषेध की मूल अवधारणा को प्रमुखता प्रदान करते हुए मादक पदार्थों की अवैधानिक बिक्री पर रोक लगायी गयी है।

(13) मेरी सरकार आयुष चिकित्सा पद्धति का विस्तार कर राज्य के सभी नागरिकों को सस्ती एवं सुलभ दुष्परिणाम रहित चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु प्रयासरत है। आयुष चिकित्सक प्रदेश के दुर्गम एवं अति दुर्गम क्षेत्रों पर चिकित्सा सेवायें प्रदान कर रहे हैं।

- जड़ी–बूटियों का भण्डार होने के कारण उत्तराखण्ड को हर्बल राज्य घोषित किया गया है।
- राज्य में एक आयुर्वेद विश्वविद्यालय एवं चार परिसर सहित तेरह आयुर्वेदिक कॉलेज स्थापित हैं।
- कोटद्वार चरक डॉडा में अन्तर्राष्टीय शोध संस्थान की स्थापना की गयी है एवं शोध संस्थान के संचालन हेतु पदों का सृजन भी कर दिया गया है।

(14) मेरी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं के दृष्टिगत विभिन्न क्षेत्रों में उपकेन्द्र के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, ट्रामा सेन्टरों व ब्लड बैंक की स्थापना कर रही है।

- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत पाँच लाख सैंतीस हजार छः सौ बानवे चयनित परिवारों को सूचीबद्ध चिकित्सालयों एवं ग्राहक

सेवा केन्द्र (सी0एस0सी0) के माध्यम से गोल्डन कार्ड बनाने की प्रक्रिया गतिमान है।

- अस्पताल में भर्ती होने पर पॉच लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष का निःशुल्क उपचार प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। 153 सरकारी एवं निजी चिकित्सालयों को सूचीबद्ध कर आवश्यक जानकारी हेतु हेल्प लाइन 104 स्थापित किया गया है।
- ''अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना'' के अन्तर्गत प्रदेश के ऐसे समस्त परिवार, जिन्हें समान प्रकृति की योजनाओं में सम्मिलित नहीं किया गया है, को अस्पताल में भर्ती होने पर ₹ 5.00 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष तथा राजकीय कर्मचारियों, अधिकारियों एवं पेंशनरों को असीमित धनराशि का स्वास्थ्य उपचार एवं निःशुल्क डायग्नोस्टिक लैब की सुविधा अनुमन्य की जायेगी। इस सम्बन्ध में चिकित्सालयों को चिन्हित किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।
- ई–औषधि द्वारा अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता एवं निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया जा रहा है।
- हैल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना द्वारा लोक निजी सहभागिता के जिला चिकित्सालय टिहरी बौराड़ी सहित दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को एक समूह के रूप में संचालित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।
- पण्डित दीन दयाल उपाध्याय, जिला चिकित्सालय, देहरादून एवं बेस चिकित्सालय, अल्मोडा में कार्डियक केयर यूनिट की स्थापना पी0पी0पी0 मोड में की गयी है। बी0पी0एल0 रोगियों का निःशुल्क परीक्षण किया जा रहा है।
- पंडित दीन दयाल उपाध्याय देव भूमि 108 आपातकालीन सेवा के अन्तर्गत 138 एम्बुलेन्स द्वारा तत्काल प्राथमिक उपचार प्रदान करते हुए रोगियों को निकटस्थ अस्पतालों में पहुँचाया जा रहा है। यह सुविधा टोल फ्री न0–108 पर उपलब्ध करायी जा रही है। 61 नई **एम्बुलेन्स** (बी0एल0एस0) क्रय की जा चुकी हैं एवं **78 एम्बुलेंस** क्रय करने की प्रक्रिया गतिमान है।

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों के संचालन हेतु पॉच सौ अट्ठावन करोड़ की धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों, आर.सी.एच. के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधायें प्रदान की जा रही है।
- स्वास्थ्य से सम्बन्धित जानकारी एवं समस्याओं के निराकरण हेतु 104 टोल फ्री सेवा उपलब्ध करायी गयी है।

(15) मेरी सरकार द्वारा राज्य के समस्त राशन कार्डों को शत–प्रतिशत ऑनलाइन डिजिटाइजेशन करते हुए राशन कार्डों को आधार नम्बर से लिंक किया गया है।

- सप्लाई चेन ऑटोमेशन के अन्तर्गत एण्ड–टू–एण्ड कम्प्यूटराइजेशन के अन्तर्गत सप्लाई चेन (एफ0सी0आई0/बेस गोदाम से आन्तरिक गोदाम तक) रियल टाइम क्रियान्वयन प्रारम्भ किया गया है।
- एफ0पी0एस0 ऑटोमेशन राज्य के समस्त 9304 राशन की दुकानों को सिस्टम इन्टिग्रेटर प्रारम्भ (सी0एस0सी0) के माध्यम से ऑटोमेट किया जा रहा है। देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर एवं नैनीताल की समस्त राशन की दुकानों को ऑटोमेट करते हुए आधार ऑथेन्टिकेशन के द्वारा काइन्ड डी0बी0टी0 किये जाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
- राज्य खाद्य योजना में कैश डी0बी0टी0 प्रारम्भ की जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही चावल की सब्सिडी की धनराशि कार्ड धारकों के एकाउन्ट में सीधे हस्तान्तरित की जा रही है।
- प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से वंचित निर्धन परिवारों हेतु राज्य उज्जवला योजना के अन्तर्गत निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किये जा रहे हैं एवं इस योजना में दस करोड़ रूपये का बजट प्राविधानित है।
- मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत कृषकों से गेहूँ एवं धान की ऑनलाइन खरीद का साफ्टवेयर तैयार किया गया है। मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत

किसानों से 1.09 लाख मीट्रिक टन गेहूँ तथा खरीद वर्ष 2018–19 हेतु धान की खरीद की गई है।

(16) गरीबी उन्मूलन के कार्यो को क्रियान्वित किये जाने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण अकुशल श्रमिकों को श्रम रोजगार उपलब्ध कराने हेतु महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना, ग्रामीण संयोजकता को पूर्ण करने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बी.पी.एल. परिवारों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने एवं आवास उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) संचालित की जा रही है।

- मेरी सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजनान्तर्गत ग्रामीण महिलाओं को सक्षम और प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान कर उनकी आजीविका में निरन्तर वृद्धि करने, वित्तीय सेवाओं तक उनकी बेहतर और सरल तरीके से पहुँच बनाने और उनकी पारिवारिक आय को बढ़ाने आजीविका के स्थायी अवसर मुहैया करा रही है।
- विभिन्न चरणों में 60 विकास खण्डों को सघन विकासखण्ड की रणनीति के अन्तर्गत अठ्ठारह हजार चार सौ तीस स्वयं सहायता समूहों का गठन कर एक हजार पॉच सौ अस्सी समूहों को रिवाल्विंग धनराशि उपलब्ध कराया गया है।
- केन्द्रांश एवं राज्यांश की उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष 9832 किमी0 लम्बाई के 1136 कार्यों पर तीन हजार छः सौ पैंतालिस करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं तथा 250 से अधिक आबादी की 1187 बसावटों को संयोजित किया गया है।
- एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना से उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों में गरीबी को कम करना है। परियोजना का क्रियान्वयन उत्तराखण्ड के अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत, नैनीताल, चमोली, रूद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी एवं देहरादून जनपदों के चयनित 44 विकासखण्डों में किया जा रहा है। परियोजना की कुल लागत आठ सौ उनहत्तर करोड़ रुपये है।

(17) मेरी सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों का चयन कर पुरस्कृत कर रही है।

- भारत सरकार द्वारा स्वीकृत जनपद हरिद्वार में कामकाजी महिला छात्रावास भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कर संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है।
- गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना "प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना" से अब तक 56653 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।
- प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना "राष्ट्रीय पोषण मिशन" का प्रारम्भ किया गया है।
- बेटी बचाओं बेटी पढाओं अभियान के अन्तर्गत 307 बालिकाओं को कम्प्यूटर टेबलेट वितरित किये गये हैं। विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस के अवसर पर 5000 सेनेटरी किट वितरित किये गये हैं।
- कन्याओं के प्रति समाज की धारणाओं को परिवर्तित कर लिंग अनुपात की असमानता में कमी लाने, महिला साक्षरता में वृद्धि, बाल विवाह को समाप्त करने तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु"नंदा गौरा योजना" प्रारम्भ की गयी है।
- कुपोषण से मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान आरम्भ किया गया है।

(18) राज्य में 5 राजकीय विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं। जनपद पौड़ी गढवाल के पावौ में नवीन राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की गयी है। अशासकीय महायोगी गुरू गोरखनाथ महाविद्यालय, बिथ्याणी (यमकेश्वर) पौड़ी गढवाल को शासकीय महाविद्यालय का दर्जा प्रदान किया है। इस प्रकार राज्य में वर्तमान में राजकीय महाविद्यालयों की संख्या 102 तथा अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की संख्या 17 हो गयी है।

- महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों हेतु ई–सेवा पुस्तिका (ऑनलाइन) आरम्भ की गयी है एवं महाविद्यालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष पठन–पाठन सुचारू रूप से चलाने हेतु गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था की गयी है।
- उच्च शिक्षा विभाग एवं पतंजलि विश्वविद्यालय के सहयोग से ज्ञान कुम्भ–2018 का सफल आयोजन किया गया।
- विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति एवं गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु आर0टी0ई0 मानकानुसार 255 प्राथमिक एवं 46 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को विलीनीकृत किया गया जिससे सरप्लस समायोजित किये जाने के कारण शिक्षकों के पदों की मानकानुसार पूर्ति की गयी।
- शिक्षा की गुणवत्ता एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के दृष्टिगत उत्तराखण्ड बोर्ड एवं सी0बी0एस0सी0 बोर्ड से मान्यता प्राप्त समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रारम्भ से कक्षा 12 तक एन0सी0ई0आर0टी0 की पुस्तकें लागू कर कक्षा 3 से कक्षा 12 तक विज्ञान विषय को क्रमोत्तर रूप से अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है।
- प्रत्येक शनिवार को समस्त राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी बोलने का दिवस एवं शंका समाधान दिवस का आयोजन कर सामान्य अंग्रेजी में बोल–चाल को प्रोत्साहन दिया जा रहा है एवं छात्रों की शंकाओं का निवारण किया जा रहा है।
- राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय योजनाओं तथा छात्रवृत्ति, पाठ्य पुस्तकों आदि की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे छात्र–छात्राओं के खाते में हस्तान्तरित की जा रही है।

- बच्चों में एनीमिया की कमी को दूर करने तथा आयरन की पर्याप्त मात्रा प्राप्त करने के लिए मध्याह्न भोजन के अन्तर्गत बनने वाले व्यंजन को लोहे की कढ़ाई में बनाये जाने के निर्णय से छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया है।

(19) मेरी सरकार राज्य के बेरोजगार युवकों को कौशल विकास से संबन्धित भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त विभिन्न योजनाएं जैसे पॉलिटेक्निक के माध्यम से सामुदायिक विकास, कम्यूनिटी कॉलेज तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आदि योजनाओं का सफलता पूर्वक संचालन किया जा रहा है।

- इलेक्ट्रॉनिक्स लर्निगं सेन्टर के माध्यम से दूरस्थ पॉलिटेक्निक संस्थाओ में विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण कार्य सम्पादित किया जा रहा है।
- मोबाइल एप की सहायता से विभिन्न पॉलीटेक्निक संस्थाओं में छात्रों को अपनी क्षमता के आंकलन, परीक्षा की तैयारी हेतु ऑनलाइन टेस्टों का आयोजन तथा प्रशिक्षण इत्यादि कार्य संचालित किये जा रहे हैं।
- विभिन्न उद्योगों से सामन्जस्य स्थापित करने हेतु सभी पॉलिटेक्निक संस्थाओं में आई0आई0आई0 सेल (उद्योग संस्थान वार्ता प्रकोष्ठ) की स्थापना की गयी है।
- राज्य में तकनीकी शिक्षा के उन्नयन हेतु तकनीकी विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु इच्छुक छात्र–छात्राओं को उन्नत तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के अतिरिक्त रोजगारपरक शिक्षा के साथ–साथ छात्रों के अन्य प्रदेशों में पलायन में काफी कमी आयी है। विश्वविद्यालय तकनीकी शिक्षा के साथ–साथ वैश्विक मांग के अनुरूप रोजगारपरक व्यावसायिक शिक्षा एम.बी.ए., बी.एच.एम.सी.टी., एप्लायड साइंस में मास्टर डिग्री आदि के अतिरिक्त शोधपरक शिक्षा को बढावा देने का कार्य कर रहा है।

- तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम फेस तीन के अंतर्गत विश्वविद्यालय एवं अन्य चयनित तकनीकी संस्थानों का सुदृढीकरण तथा शैक्षिक अनुसंधान के कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं। संस्थानों को सेंटर आफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है।

(20) मेरी सरकार राज्य में संस्कृत को बढ़ावा दिये जाने हेतु प्रतिबद्ध है। राज्य में 97 संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालय संचालित किये जा रहे हैं, जिनमें 01 केन्द्रीय महाविद्यालय, 75 अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय एवं 14 वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालय सम्मिलित हैं।

- संस्कृत शिक्षा के सार्वभौमिकरण की दृष्टि से राज्य में संस्कृत शिक्षा परिषद् द्वारा परिषदीय परीक्षाओं का सफल आयोजन किया गया है।
- हाईस्कूल/इण्टर में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को "गवर्नर्स अवार्ड, 2018" तथा 5 शिक्षकों को "गवर्नर्स टीचर्स अवार्ड, 2018" से सम्मानित किया गया है।
- राज्य में संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊँ मण्डल में एक–एक राजकीय आदर्श संस्कृत विद्यालय उत्तर मध्यमा तक खोला जाना प्रस्तावित है।
- राज्य में संस्कृत भाषा को लोक भाषा बनाने हेतु चमोली के किमोठा तथा बागेश्वर के भैन्तोला गांव को संस्कृत ग्राम तथा हरिद्वार एवं ऋषिकेश को संस्कृत नगरी घोषित किया गया है।
- संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दिये जाने एवं उसके प्रचार–प्रसार के दृष्टिगत राज्य के समस्त कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों एवं पर्यटन क्षेत्रों में बोर्डो तथा नाम पट्टिकाओं पर हिन्दी भाषा के साथ–साथ संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया गया है।

(21) मेरी सरकार ने उत्तराखण्ड के लेखकों को पुस्तक प्रकाशन हेतु उत्कृष्ट पुस्तक प्रकाशन आर्थिक अनुदान, साहित्यकारों को उनकी स्वरचित कृतियों के लिए लोक भाषाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कार्यशालाएँ एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, विभिन्न स्थानों पर लोक भाषा सम्मेलनों का आयोजन, एवं संस्थान की शोध पत्रिका उद्गाता का प्रकाशन किया है।

- उत्कृष्ट पुस्तकों के प्रकाशन हेतु आर्थिक अनुदान प्रदान करना तथा मदरसों/उर्दू मीडियम स्कूलों में छात्रों के उपयोगार्थ पुस्तकों का क्रय किया गया है।
- मौलिक ग्रन्थ प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता, साहित्यकारों को आर्थिक अनुदान, हिन्दी सम्मेलन, हिन्दी दिवस प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रही है।
- पंजाबी साहित्यकारों की गोष्ठी, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पंजाबी सम्मेलन, पुरस्कार पंजाबी साहित्यकारों का सम्मान, उत्कृष्ट पुस्तक का प्रकाशन किया गया है।

(22) मेरी सरकार द्वारा कृषि को विकसित करने एवं वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देते हुए जलसम्भरण से सम्बन्धित कार्य वर्मी कम्पोस्ट निर्माण हेतु 2000 हेक्टेयर क्षेत्रफल विस्तार कर 2972 कुन्तल आलू, अदरख, लहसुन बीज वितरण, मशरूम उत्पादन हेतु 59 मीट्रिक टन पाश्चुराईज्ड कम्पोस्ट का उत्पादन कर वितरण, 370 किलोग्राम स्पॉन वितरित कर 1316 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

- रवि एवं खरीफ फसलों की बीमा कर सत्तावन हजार उद्यानपतियों को बीमा से आच्छादित किया गया है।
- ग्रीन हाउस की पॉलीथीन बदलाव योजना के अन्तर्गत पुराने जीर्ण शीर्ण पॉलीहाउस की पॉलीथीन बदलने हेतु राजसहायता दी जा रही है।
- मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना के अन्तर्गत चौबीस हजार वर्ग मी० पॉलीहाउस की स्थापना हेतु राज सहायता प्रदान की गयी है।

- पर्वतीय क्षेत्रों में बेमौसमी सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु 1.00 हेक्टेयर तक 75 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।

- नई पौधशालाओं की स्थापना को बढ़ावा देने हेतु 50 प्रतिशत एवं अधिकतम ₹ सात लाख पचास हजार प्रति हेक्टेयर एवं छोटी पौधशाला हेतु अनुपातिक राजसहायता प्रदान की जा रही है।

- उच्च तकनीकी द्वारा सेब उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु एप्पल मिशन योजना के अन्तर्गत उद्यानपतियो को 1 एकड़ तक 80 प्रतिशत आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है।

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत 1595 हेक्टेयर में ड्रिप स्प्रिंकलर प्रणाली से 2200 कृषकों को लाभान्वित किया गया हैं।

- बागवानी के समग्र विकास हेतु विश्व बैंक पोषित योजनान्तर्गत सात सौ करोड़ रुपये का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

- कृषकों की आय वर्ष 2022 तक दोगुनी करने हेतु संकल्प से सिद्धि यात्रा का शुभारम्भ कर दिया गया है, कृषि एवं अन्य रेखीय विभागों का माइक्रो प्लान तैयार करने की कार्यवाही गतिमान है।

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु निवेश आकर्षित करते हुए 66 उद्यमियों से दो हजार सात सौ सोलह करोड़ रुपये के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 60 उद्यमियों द्वारा रूपये दो हजार चार सौ करोड़ के अनुबन्ध किये गये हैं एवं 19 उद्यमियों द्वारा चार सौ करोड़ रुपये के कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं।

- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत एरोमा प्रासेसिंग भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसमें कृषकों, उद्यमियों को विभिन्न प्रकार की आसवन सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी। उत्तराखण्ड विशिष्ट फसल का प्रसंस्करण

कर सुगन्धित तेल, ओलेरोसीन हर्बल उद्धरण तैयार कर सगन्ध तेल आधारित नये उत्पादों को तैयार किया जा रहा है।

- कार्मिकों को जड़ी–बूटी के अधीन विकसित नई तकनीकियों से भिज्ञ कराये जाने एवं उनकी तकनीकी दक्षता में वृद्धि करने के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर में प्रशिक्षण आयोजित कराया गया है।
- देश–विदेश में जैविक चाय की मॉग को दृष्टिगत रखते हुए जैविक चाय की खेती को प्रोत्साहन दिये जाने का निर्णय लिया गया है। नौटी, घोड़ाखाल एवं चम्पावत चाय बागानों के 485 हेक्टेयर क्षेत्रफल को जैविक चाय हेतु परिवर्तित कर दिया गया है।
- भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय सम्पोषणीय कृषि मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के सात जनपदों में 59 क्लस्टर्स का गठन कर जैविक रेशम का प्रोत्साहन, प्रसंस्करण, मूल्य सम्बर्द्धन और प्रमाणीकरण प्रबन्धन द्वारा क्लस्टर व समूह के रूप में संस्था को विकसित करते हुए सशक्त बनाया गया है।

(23) मेरी सरकार राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं कर अपवंचना, कानून का उल्लघंन करने वाले वाहनों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर रही है।

- वाहन चालकों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण की व्यवस्था दिये जाने हेतु हल्द्वानी में एक वृहत चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु तेइस सौ करोड़ रुपये की धनराशि का प्रस्ताव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।
- प्रदेश के सभी संभागीय एवं उपसंभागीय कार्यालयों में वाहन सॉफ्टवेयर का "वाहन 4.0" (वैब आधारित) वर्जन लागू किया गया है।
- **वार्षिक बजट में पॉच प्रतिशत सड़क सुरक्षा के लिये प्राविधान** किया जाना **प्रस्तावित किया गया है।**

- उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य्य परिवहन करार सम्पन्न किया गया है तथा भारत–नेपाल के परिवहन करार सम्पन्न करते हुए उत्तराखण्ड राज्य से परिवहन सेवाओं का प्रारम्भ कर दिया गया है।
- उत्तराखण्ड राज्य में अन्य प्रदेश से आने वाली व्यवसायिक वाहनों द्वारा ऑन–लाइन कर भुगतान की व्यवस्था की गयी है।
- राज्य के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में बसों का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है।
- परिवहन निगम की बसों में छात्राओं को शिक्षण संस्थान के नजदीक के बस स्टॉप से उनके स्थानीय निवास के नजदीकी बस स्टाप तक निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है।
- भारत सरकार के प्राथमिकता कार्यक्रम के अन्तर्गत बसों में नगदी रहित भुगतान की सुविधा पेटीएम के माध्यम से टिकट निर्गत किये जा रहे है।
- देहरादून–मसूरी एवं हल्द्वानी–नैनीताल मार्ग पर विद्युत बसों का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है।

(24) राज्य में पर्यटन के विकास हेतु सहस्त्रधारा हैलीपैड से श्री केदारनाथ दर्शन, हेमकुण्ड साहिब दर्शन के लिये हैली सेवायें संचालित की गयी है। जिससे उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की आय में 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा यात्री किराये में कमी आयी है।

- राज्य में एयर फील्ड कनेक्टिविटी के अन्तर्गत जौलीग्रान्ट, चिन्यालीसौड, गौचर में वायुयान सेवायें प्रारम्भ किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है, देहरादून से पन्तनगर एवं नैनीसैनी पिथौरागढ़ हवाई सेवा प्रारम्भ कर दी गयी है।

(25) मेरी सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के निर्धन परिवारों के बच्चों के शैक्षिक विकास हेतु 22 आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन कर रही है।

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के निर्धन छात्रों को शिक्षा, अध्ययन सामग्री, आवास, भोजन, वस्त्र आदि की सुविधाएं निःशुल्क प्रदान कर रही है।
- अनुसूचित जाति के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से सी.बी.एस.सी. पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 12 तक की शिक्षा दिये जाने के उद्देश्य से राजकीय आदर्श आवासीय विद्यालय मक्खनपुर हरिद्वार के संचालन की प्रक्रिया गतिमान है।
- अनुसूचित जाति के छात्रों को विभिन्न व्यवसायों में रोजगारपरक तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के उददेश्य से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित किये जा रहे हैं।
- ऐसे किसान जो स्वयं की भूमि पर खेती कर रहे है उनको एक हजार प्रतिमाह किसान पेंशन स्वीकृति की जा रही है।
- निराश्रित विधवाओं को पेंशन के साथ–साथ उनकी पुत्रियों के विवाह हेतु पचास हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है।

(26) मेरी सरकार अल्पसंख्यक वर्गों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में उनकी विशिष्ट समस्याओं का निराकरण करने एवं उनका शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु वचनबद्ध है।

- पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना शत–प्रतिशत राज्य सहायतित के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा 10 तक के ऐसे सभी छात्रों, जिनके अभिभावकों की आय गरीबी रेखा के लिये निर्धारित आय सीमा के दोगुना से अधिक नहीं हो, को छात्रवृति दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

- अल्पसंख्यक क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराने, शैक्षिक विकास करने हेतु चार सौ करोड़ रूपये से अल्पसंख्यक विकास निधि की स्थापना की गयी है।
- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों की मेधावी बालिकाओं की शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु साठ प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को पचीस हजार रूपये का विशेष अनुदान दिया जा रहा है।
- अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियो के लिए सरकारी सेवा की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तथा राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से प्रवेश लेने हेतु प्रोत्साहन के रूप में अधिकतम पचहत्तर हजार रूपये की धनराशि दी जा रही है।
- केन्द्र सहायतित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना मुख्य रूप से गरीबी उन्मूलन, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल एवं आपूर्ति स्वच्छता कार्यक्रम अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में संचालित किये जा रहे हैं।

(27) मेरी सरकार पूर्व सैनिकों, शहीदों तथा उनके आश्रितों के लिए कल्याण एवं पुनर्वास की सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु कार्यशील है।

- पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के कल्याण हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। अभ्यर्थियों को भर्ती पूर्व प्रशिक्षण हेतु कैम्प लगाये गये हैं। प्रतिवर्ष पाँच सौ अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।
- **मेरी सरकार ने वीरता पदक पुरस्कार में** एक मुश्त एवं वार्षिकी में अभूतपूर्व वृद्धि की है तथा वार्षिकी जो पूर्व में 30 वर्षो तक के लिए अनुमन्य थी उसे आजीवन कर दिया गया है। उत्तराखण्ड राज्य आज देश का सबसे अधिक अनुदान देने वाले राज्यों में से एक है।

- आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु द्वितीय विश्व युद्ध के नान पेंशनर व विधवाओं को आठ हजार प्रतिमाह की दर से पेंशन, अनुदान का भुगतान अनुमन्य किया गया है।
- कम्प्यूटर प्रशिक्षण को और अधिक रोजगार परक बनाने के लिए पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया है। सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रित हेतु प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है। 343 भूतपूर्व सैनिक एवं उनके आश्रित प्रशिक्षण ले रहे हैं ।
- राज्य के पूर्व सैनिकों को गृहकर में छूट दी गयी है।

(28) राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में खेल महाकुम्भ में तीन लाख अस्सी हजार खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। 800 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में विजयी खिलाड़ियों को 95 स्कूटर एवं उपविजेता खिलाड़ियों को 95 साइकिल प्रदान की गयी तथा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बालक–बालिका को एक्यावन–एक्यावन हजार रुपये की नगद राशि दी गयी है।

- अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत 200 युवाओं को रोजगारपरक योजना में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
- प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयं सेवकों को विभिन्न शासकीय कार्यालयों, प्रतिष्ठानों में सेवायें उपलब्ध कराते हुए चार हजार स्वयं सेवकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।
- प्रदेश की 7951 ग्राम पंचायतों में 4995 युवक मंगल दल तथा 5381 महिला मंगल दलों को विभाग के अंतर्गत सम्बद्धीकृत किया गया है।
- राज्य स्तरीय साहसिक प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से 164 युवाओं को राफ्टिंग, आपदा प्रबन्धन एवं प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षित किया गया है।

(29) मेरी सरकार राज्य की ऐतिहासिक, पौराणिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण–संवर्द्धन एवं उसका सर्वांगीण विकास एवं पोषण करने हेतु प्रतिबद्ध है।

- राज्य में एक संस्कृति ग्राम बनाया जायेगा जिसमें एक ही स्थान पर प्रदेश की गौरवमयी संस्कृति की अनुभूति हो सकेगी।
- वीरांगना तीलू रौतेली के नाम पर वीरौंखाल में उनके शौर्य एवं संघर्ष से जुड़ी वर्णित घटनाओं को संग्रहीत किये जाने हेतु संग्रहालय स्थापित करेगी।
- पारम्परिक लोक सांस्कृतिक विरासत एवं लोक कला का समन्वय कर उन्हें भावी पीढ़ी के लिए संजोये रखने के उद्देश्य से सतपुली में वृहद सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना की जायेगी।
- अनाशक्ति आश्रम कौसानी में बहुउद्देशीय बापू प्रेक्षागृह एवं ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा व पण्डित सुमित्रानन्दन पन्त संग्रहालय का जीर्णोधार किया जायेगा।

(30) मेरी सरकार चारधाम यात्रा श्री यमुनोत्री–गंगोत्री–केदारनाथ–बद्रीनाथ तथा हेमकुण्ड–लोकपाल, नानकमत्ता, रीठा साहिब एवं पिरान कलियर नामक विभिन्न धर्मो के पवित्र तीर्थ स्थलों से युक्त इस प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु वचनबद्ध है।

- ग्रामीण व पहाड़ी क्षेत्रों से पयालन रोकने के उद्देश्य से "दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना" प्रारम्भ कर स्थायी मूल निवासियों हेतु नये होम स्टे निर्माण अथवा भवनों के सुदृढ़ीकरण हेतु बैंक से ऋण अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है। योजनान्तर्गत प्रत्येक जनपद को ₹ 25 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।
- वर्ष 2020 तक पूरे प्रदेश में 5000 होम स्टे विकसित कर पंजीकृत किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें 723 होम स्टे पंजीकृत किये जा चुके हैं।

डेस्टिनेशन्स की थीम विकसित करने हेतु प्रत्येक जनपद को ₹ 50 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है।

- श्री केदारनाथ धाम के सुनियोजित विकास हेतु "श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट" की स्थापना की गयी है।
- नीति आयोग के माध्यम से ऋषिकेश में आई0डी0पी0एल0 में कन्वेंशन सेन्टर की स्थापना हेतु चयन किया गया है।
- प्रसाद योजना के अन्तर्गत बद्रीनाथ में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु उनतालीस करोड़ की योजना पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।
- पूर्णागिरी रोप वे एवं कद्दूखाल–सुरकण्डा देवी रोप वे परियोजनाओं का निर्माण कार्य पी0पी0पी0 मोड़ पर गतिमान है।
- माह अक्टूबर में आयोजित इन्वेस्टर समिट में पर्यटन के विभिन्न क्षेत्रों में तेरह हजार एक सौ अठ्ठाइस करोड़ के निवेश हेतु 105 एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किये गये है।

(31) मेरी सरकार सूचना एवं लोक सम्पर्क के माध्यम से जनता में समन्वय स्थापित करते हुए सरकार की नीतियों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी विभिन्न माध्यमों से जन–जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है।

- मान्यता प्राप्त श्रमजीवी पत्रकारों एवं सक्रिय पत्रकारों को पत्रकार कल्याण कोष से आर्थिक सहायता तथा राजकीय चिकित्सालयों में सरकारी कर्मचारियों की भाँति चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है।
- असाध्य रोगों से पीड़ित पत्रकारों को उनके इलाज के लिए आर्थिक सहायता एवं मृत्यु होने की दशा में उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता भी

प्रदान की जा रही है। परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जा रही है।

- राज्य में शूटिंग शुल्क को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया है। शूटिंग हेतु अनुमति सिंगल विन्डो के माध्यम से प्रदान की जा रही है।
- राज्य सरकार के विकास कार्यों एवं नीतियों की जानकारी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से आम जनता तक पहुँचायी जा रही है।

(32) मेरी सरकार ग्राम स्तर पर गठित दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से दो लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध उपार्जन कर रही है, दुग्ध उत्पादकों को सोलह करोड़ रूपये का दुग्ध मूल्य का भुगतान प्रतिमाह प्राप्त किया जा रहा है।

- दुग्ध सहकारी समिति की 1390 महिला सदस्यों को गंगा गाय महिला डेरी योजनान्तर्गत दुधारू गाय क्रय करने हेतु 27 हजार रुपये प्रति गाय की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी गयी है। आगामी वर्ष में 1400 महिला दुग्ध उत्पादकों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।
- प्रदेश में दुग्ध सहकारिताओं के सम्पूर्ण विकास एवं उनकी आवश्यकताओं के दृष्टिगत 5 से 10 दुधारू पशुओं की यूनिट स्थापना के लिए ऋण एवं 20 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत 3050 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा।
- प्रदेश में पहली बार दुग्ध सहकारी समिति स्तर पर दूध को ठंडा रखने के उद्देश्य से रेफ्रीजरेटेड मिल्क केन की स्थापना की जानी प्रस्तावित है।
- प्रदेश के दुग्ध संघों की आय में वृद्धि हेतु अमूल गुजरात से समझौता कर कार्मिकों की कार्य दक्षता बढ़ाये जाने हेतु उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है।

(33) मेरी सरकार का मत्स्य पालन व्यवसाय को विस्तारित किये जाने हेतु भारत सरकार के मिशन ब्लू रिवोल्यूशन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022 तक मत्स्य उत्पादन एवं मत्स्य पालकों की आय को दोगुना किये जाने का लक्ष्य है।

- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत ट्राउट मत्स्यिकी विकास हेतु तीन सौ चौबीस लाख का प्रोजेक्ट संचालित किया गया है। महिला सशक्तीकरण हेतु महिला समूहों को मात्स्यिकी क्षेत्र में जोड़ा जा रहा है।
- एंग्लिग पर्यटन से रोजगार सृजन तथा मात्स्यिकी संरक्षण को बढ़ाने हेतु राज्य की नदियों में चिन्हित बीटों को स्थानीय समूहों को आंवटित किया गया है।
- मत्स्य प्रसंस्करण व्यवसाय को स्थापित किये जाने हेतु मोबाइल फिश आउटलेट प्रारम्भ किये गये हैं। मत्स्य उत्पादन वृद्धि हेतु पंगेशियस, आमूर कार्प, आदि उन्नत प्रजातियॉ के पालन को प्रोत्साहित कर रही है।
- राज्य का प्रथम ब्रूड बैंक (कार्प प्रजाति) का निर्माण पूर्ण कर प्रथम ट्राउट ब्रूड बैंक के स्थापना की कार्यवाही गतिमान है।

(34) प्रदेश के उपखनिज क्षेत्रों के आवंटन में पारदर्शिता लाने तथा राजस्व वृद्धि एवं रोजगार के दृष्टिगत राज्य के रिक्त उपखनिज क्षेत्रों को ई–निविदा/सह ई–नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु नियम बनाये गये हैं।

- खनिजों से दो सौ चौबीस करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है। इसके साथ ही 2512 खनन के क्षेत्रीय निरीक्षण से सम्बन्धित प्रकरणों तथा भू–अभियांत्रिकीय कार्य योजना के अन्तर्गत 615 क्षेत्रीय निरीक्षण के प्रकरणों का निस्तारण किया गया है।
- अवैध खनन, परिवहन की रोकथाम हेतु आधुनिक निगरानी युक्त चैक पोस्ट संवेदनशील खनन स्थलों पर स्थापित किये गये हैं। प्रथम चरण में राज्य में अवैध खनन की रोकथाम हेतु ई–रवन्ना प्रणाली लागू कर दी गयी है।

- प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु खनन से प्रभावित क्षेत्रों के विकास हेतु जिला स्तर पर खनिज न्यास का गठन किया गया है। खनन से उन्नीस करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है, खनिज प्रभावित क्षेत्रों के विकास कार्यो में सैंतालिस लाख का व्यय किया गया है। विभिन्न जनपदों में योजनान्तर्गत अद्यतन कुल 120 योजनायें स्वीकृत हेतु गतिमान है।
- ई0आई0ए0 योजना के अन्तर्गत राजस्व एवं वन क्षेत्र में उपलब्ध अधिक से अधिक उपखनिज क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए उनका आवंटन ई–नीलामी के माध्यम से कराये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।

(35) मेरी सरकार राज्य में पारिस्थितिकीय पर्यटन को राजस्व अर्जन के साथ–साथ स्थानीय निवासियों की आय में वृद्धि के स्रोत की दृष्टि से फूलों की घाटी पार्क में भ्यूंडार गाँव में ईको डेवलपमेन्ट कमेटी, छोटी हल्द्वानी में होमस्टे तथा मसूरी के निकट धनोल्टी ईको पार्क का सफलता पूर्वक संचालन किया जा रहा है।

- जलवायु परिवर्तन के अनुरूप वानिकी, कृषि, उद्यानीकरण, जलसंचय, आपदा, सड़क, यातायात, स्वास्थ्य एवं पेयजल सेक्टर में कार्य योजनाओं का निरूपण कर क्रियान्वयन रेखीय विभागों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन कार्यसूची में पूर्ण कर लिया गया है।
- गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के स्वीकृत प्रकरणों में मुख्य रूप से क्षतिपूरक वनीकरण, दण्डात्मक क्षतिपूरक वनीकरण, अन्य स्थल विशिष्ट कार्य, कैट प्लान, संरक्षित क्षेत्रों का विकास एवं एन0पी0वी0 के तहत गतिविधियां सम्पन्न करायी जानी प्रस्तावित है।
- जायका परियोजना का मुख्य उद्देश्य चयनित वन पंचायतों से लगे हुए अवनत वनों की दशा में सुधार तथा सम्बन्धित ग्राम समुदाय की आजीविका व आय में वृद्धि के उपाय सुनिश्चित करते हुए वनों का चिरस्थाई प्रबन्धन करना है।

- राजाजी नेशनल पार्क को दो करोड़ पचास लाख एवं बारह करोड़ कॉर्बेट नेशनल पार्क को राज्य सहायता के रुप में दी जायेगी।
- कॉर्बेट नेशनल पार्क एवं राजाजी नेशनल पार्क से प्राप्त राजस्व राजकोष में जमा किया जायेगा।

(36) मेरी सरकार प्रदेश की जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु कटिबद्ध है। बाइस हजार बस्तियाँ पूर्ण सेवित कर दी गई हैं। सत्रह हजार बस्तियाँ आंशिक रूप से सेवित की गई हैं एवं 710 आंशिक सेवित ग्रामीण बसावटों को पेयजल सुविधा से आच्छादित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित है।

- दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त 1240 पेयजल योजनाओं को तत्काल अस्थायी व्यवस्था से चालू किया गया है।
- जल संचय तथा जल संरक्षण–संवर्धन अभियान के अन्तर्गत 400 चाल–खाल निर्मित की जा चुकी है।
- चारधाम यात्रा के दौरान यात्रा मार्गो पर स्थापित 246 टेंक टाईप स्टेण्ड पोस्ट (टी.टी. एस.पी.), 457 पिलर टाईप स्टेण्ड पोस्ट (पी.टी.एस.पी.), 863 हैण्डपम्पों तथा 46 चरही में सुचारू जलापूर्ति की व्यवस्था की गयी हैं।
- संयोजनों में ए.एम.आर. तकनीक आधारित जलमापक यंत्र स्थापित किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य का परिव्यय के सापेक्ष राज्य सरकार की अच्छी प्रगति के दृष्टिगत प्रोत्साहन धनराशि के रूप में सत्ताइस करोड़ पैंतीस लाख रूपये की अतिरिक्त धनराशि प्रदान की गयी है। वर्ष 2018–19 हेतु भी वार्षिक परिव्यय बढ़ाकर निन्यानवे करोड़ सत्रह लाख किया गया है।

- बाह्य सहायतित परियोजना के माध्यम से राज्य के 35 अर्द्धनगरीय क्षेत्रों हेतु विश्व बैंक सहायतित परियोजना (अनुमानित लागत नौ सौ पचहत्तर करोड़) स्वीकृत कराई गई। परियोजना के अन्तर्गत डी0पी0आर0 स्वीकृति की कार्यवाही गतिमान है।

- राज्य के समस्याग्रस्त नगरीय एव ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पेयजल योजनाओं के वित्त पोषण हेतु एक हजार करोड़ रूपये लागत की बाह्य सहायतित परियोजनाओं का प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार की सहमति हेतु भेजा गया है।

- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लक्ष्यित तिथि 02 अक्टूबर, 2019 से पूर्व ही 'खुले में शौच की प्रथा से मुक्त' घोषित होने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है।

- पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वच्छ ऑईकोनिक स्थल गंगोत्री को 'स्वच्छ भारत राष्ट्रीय पुरस्कार' के अन्तर्गत 'विशिष्ट स्वच्छ ऑईकोनिक स्थल' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

- ग्रामीण बस्तियों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन की योजना के अन्तर्गत दो हजार दो सौ बीस ग्राम पंचायतों की डी0पी0आर0 स्वीकृत कर दी गयी है, 129 ग्राम पंचायतों में कार्य पूर्ण हो गया है तथा शेष ग्राम पंचायतों में कार्य प्रगति पर है। कार्यक्रम के प्रभावी संचालन हेतु मनरेगा, ग्राम्य विकास विभाग, पंचायतीराज विभाग, उरेड़ा एवं कृषि विभाग के साथ केन्द्राभिसरण (Dove-tailing) के माध्यम से कार्य किया जा रहा है।

- भारत सरकार द्वारा 'नमामि गंगे परियोजना' के अन्तर्गत गंगा नदी की मुख्य धारा के किनारे स्थित 15 नगरों में पूर्व निर्मित एस.टी.पी. के उच्चीकरण, नवीन एस.टी.पी. के निर्माण तथा गन्दे नालों के एस.टी.पी. में डायवर्जन (Diversion) से सम्बन्धित 19 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं।

- गंगा नदी की मुख्य धारा में अपरिशोधित सीवर अथवा अन्य प्रदूषित जल के जाने पर पूर्ण रोक लगा देने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

- राज्य के समस्त नगरीय क्षेत्रों को सीवरेज से आच्छादित किये जाने हेतु हरिद्वार एवं ऋषिकेश में जलोत्सारण सुविधा के पूर्ण आच्छादन हेतु ग्यारह सौ पचास करोड़ रूपये की बाह्य सहायतित परियोजना का प्रस्ताव पर भारत सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अनुबन्ध निष्पादित हो गया है। डी0पी0आर0 तैयार की जा रही है।

- प्रदेश में जल स्रोतों के संरक्षण–संवर्द्धन की आवश्यकता के दृष्टिगत पेयजल, ग्राम्य विकास, वन, कृषि, जलागम आदि विभिन्न विभागों के माध्यम से चाल–खाल, जलकुण्ड, फार्म पौण्ड, कन्टूर ट्रेंच, चैक डैम तथा रेनवाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है।

- राज्य के परम्परागत जल स्रोतों, नौलों तथा धारों के संरक्षण हेतु स्वजल परियोजना के अन्तर्गत जल स्रोत मापन एवं जल स्रोतों की मैपिंग हेतु वैब पोर्टल विकसित किया गया है। वर्तमान में लगभग 4494 स्रोतों की मैपिंग तथा वर्ष 2022 तक 5000 समस्याग्रस्त प्राकृतिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित/संवर्धित करने हेतु दो सौ पचास करोड़ रूपये की लागत की परियोजना का प्रस्ताव तैयार कर केन्द्र वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत भारत सरकार को भेजा जाना लक्षित है।

(37) मेरी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ट्रांसपोर्टनगर, देहरादून में 224 एवं आमवाला तरला, देहरादून में 240 ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ कर रही है।

- आवासीय योजनाओं के निर्माण हेतु प्रति आवास एक लाख पचास हजार रूपये की दर से कुल छः सौ छियानवे लाख रुपये की अनुदान राशि केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है।

- राज्य सरकार द्वारा भी प्रत्येक आवास हेतु एक लाख रुपये की दर से कुल चार सौ चौसठ लाख रूपये की धनराशि प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए धौलास क्षेत्र में 240 ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों तथा राजपुर रोड क्षेत्र में 886 ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों के निर्माण की स्वीकृति केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गयी है।

- प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ई0डब्ल्यू0एस0 आवास निर्माण के लिये, निजी भू–स्वामियों व निजी विकासकर्ताओं को प्रोत्साहित किये जाने के उददेश्य से उत्तराखण्ड आवास नीति बनाई गई है।

- उत्तराखण्ड राज्य में मैदानी व पर्वतीय क्षेत्रों में एक समान अवस्थापकीय सुविधाओं, आवासीय सुविधाओं व पर्यटन सम्बन्धित सुविधाओं के विकास हेतु वर्ष 2031 तक विज़न डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में एकीकृत टाउनशिप विकास तथा सामाजिक व मंनोरजन सुविधाओं को विकसित किये जाने में सहायता प्राप्त होगी।

(38) मेरी सरकार द्वारा अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन अमृत योजनान्तर्गत प्रदेश के 06 नगर निगमों एवं नगर पालिका परिषद् नैनीताल हेतु पांच सौ तिरानवे करोड़ रूपये की जलापूर्ति, सीवरेज प्रबन्धन, स्ट्रॅाम वॅाटर ड्रेनेज एवं ग्रीन स्पेस पार्क की योजनायें भारत सरकार से अनुमोदित करायी गयी है।

- शहरी क्षेत्रों की स्थानीय निकायों में खुले में शौच व मैला ढोने की प्रवृत्ति का उन्मूलन, वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व स्वच्छता से संबंधित जन व्यवहार में परिवर्तन के उददेश्य से व्यक्तिगत घरेलू/सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।

- प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास शहरी योजना के अन्तर्गत आवास मांग सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया गया है अभी तक एक लाख चार हजार सात सौ इकसठ आवासों की मांग प्राप्त हुई है।

- निराश्रित श्वान पशुओं की जनसंख्या नियंत्रण हेतु ए0बी0सी0–ए0आर0वी0 कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर प्रथम चरण में देहरादून, मसूरी एवं नैनीताल शहर में श्वान पशु बन्ध्याकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

- स्थानीय निकायों के सीमान्तर्गत निवासरत लोगों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु अवस्थापना से सम्बन्धित कार्यों यथा ड्रैनेज व्यवस्था, सड़क, गलियों, नालियों का निर्माण/सुधार आदि कार्यों, के लिए धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है।

(39) मेरी सरकार द्वारा केन्द्र पोषित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत चिन्हित 94 अविद्युतीकृत राजस्व ग्रामों का विद्युतीकरण में शत–प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

- यमुना नदी पर स्थित व्यासी जल विद्युत परियोजना (120 मेगावॉट) का 65 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। परियोजना का कार्य माह दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

- मद्महेश्वर 15 मेगावाट, कालीगंगा–प्रथम 4 मेगावाट, एवं कालीगंगा–द्वितीय 4.5 मेगावाट,के निर्माण कार्य प्रगति पर है।

- प्रदेश में सौर ऊर्जा की संशोधित नीति जारी की गई है, जिसके अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों के लिए 5 मेगावॉट तक सौर ऊर्जा पावर प्लाण्टस की स्थापना हेतु नीति बनायी गई है। इस नीति से पर्वतीय क्षेत्रों में रोज़गार में वृद्धि होगी एवं पलायन रोका जा सकेगा।

- प्रदेश में वन्य अवशेषों यथा चीड़ की पत्तियों (पिरूल) से विद्युत उत्पादन हेतु पाईन निडिल एवं अन्य बायोमास आधारित ऊर्जा उत्पादन नीति–2018 जारी की जा चुकी है।

- भारत सरकार द्वारा संचालित रूफ टॉप सोलर पावर प्लाण्ट योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 4–5 किलोवाट क्षमता के 1502 संयत्रों की स्थापना की गई है।

(40) औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के साथ–साथ श्रम कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू कर, संगठित/असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को श्रम कानूनों के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है।

- श्रम कानूनों का उल्लंघन करने पर सेवायोजकों के विरुद्ध 566 उपशमन एवं अभियोजन की कार्यवाही की गयी है।

- श्रमिकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत चौतीस लाख श्रमिकों को लाभान्वित किया गया है।

- राज्य के नये क्षेत्र चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, बागेश्वर, टनकपुर एवं चंपावत में भी नवीन सर्वेक्षण के उपरान्त एक–एक औषधालय खोले जाने का प्रस्ताव राज्य बीमा निगम को प्रेषित कर दिया गया है।

(41) मेरी सरकार छात्र–छात्राओं एवं युवाओं के कौशल विकास अर्जन तथा उसमें आवश्यकतानुसार वृद्धि कर रही है।

- 46 भवन विहिन संस्थानों में निर्माण कार्य प्रगति पर है। तथा छः राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आधुनिक प्लम्बर तकनीक में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

- राज्य में प्रथम बार नवीन सैक्टरों के अन्तर्गत प्लास्टिक प्रोसेसिंग, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी, सौयल टेस्टिंग कोर्स प्रारम्भ किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।
- विश्व बैंक के सहयोग से चिन्हित 25 संस्थानों में रोजगार परक व्यवसायों को संचालित करने, स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षणार्थियों व अनुदेशकों के ऑन–ऑफ द जॉब प्रशिक्षण तथा उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं में अधिकतम क्षमता परिवर्धन हेतु 500 करोड़ रूपये की महत्वाकांक्षी योजना पर कार्यवाही गतिमान है।
- शिशिक्षु अधिनियम के माध्यम से राज्य के 475 अधिष्ठानों को केन्द्र सरकार के पोर्टल पर पंजीकृत कर 5816 चिन्हित सीटों के सापेक्ष 2241 शिशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
- 43 प्रशिक्षण संस्थान विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की साझेदारी में "पब्लिक–प्राइवेट–पार्टनरशिप" के अन्तर्गत संचालित किये जा रहे हैं।
- भारत सरकार द्वारा नेशनल कैरियर सर्विस परियोजना के अन्तर्गत युवाओं को रोजगार हेतु सक्षम बनाने के उददेश्य से प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों को मॉडल कैरियर सेन्टर के रुप में विकसित किया जा रहा है।
- भारत सरकार द्वारा जनपद अल्मोड़ा के सेवायोजन कार्यालय को मॉडल कैरियर सेन्टर के रुप में विकसित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- नेशनलई योजना गवर्नेन्स के अन्तर्गत सभी जनपदों के सेवायोजन कार्यालयों में ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था आरम्भ की जा चुकी है।

(42) मेरी सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में 413 किमी0 मार्गो का नव निर्माण, 604 किमी0 मार्गो का पुनःनिर्माण तथा 27 सेतुओं का निर्माण करते हुए 26 ग्रामों को सम्पर्क मार्गो से जोड़ा है।

- राज्य में विभिन्न श्रेणियों के अवस्थित पन्द्रह हजार सात सौ राजस्व ग्रामों में से बारह हजार तीन सौ ग्रामों को सड़क यातायात से जोड़ा गया है।
- ट्राईबल सब प्लान के अन्तर्गत सत्ताईस करोड़ की धनराशि से 19 किमी0 लम्बाई में नव निर्माण एवं 6 किमी0 लम्बाई में पुनःनिर्माण कर गांवों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ा गया है।
- बाढ़ एवं भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हुए 1815 मार्गों को यातायात हेतु उपलब्ध करा दिया गया है, शेष मार्गों का कार्य प्रगति पर है।
- मोहकमपुर में रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य पूर्ण कर यातायात को सुचारु रुप से चलाये जाने हेतु प्रारम्भ कर दिया गया है।
- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72A के डाटकाली मन्दिर के समीप दो लेन सुरंग का निर्माण कार्य पूर्ण कर यातायात हेतु खोल दिया गया है। जिसमें राज्य को तीन प्रतिशत बोनस की राशि प्राप्त होगी।
- चारधाम परियोजना हेतु 'ऑल वैदर रोड' के अन्तर्गत 346 किमी0 लम्बाई के 31 कार्यों पर कार्य प्रगति पर है। इस वित्तीय वर्ष में 18 कार्य पूर्ण किये जाने हेतु प्रस्तावित हैं।
- बहुप्रतीक्षित हरिद्वार–देहरादून मोटर मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है। आगामी वित्तीय वर्ष में कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।
- हरिद्वार–नगीना मोटर मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
- पूर्व से निर्मित "बी" श्रेणी के सेतुओं को "ए" श्रेणी में परिवर्तित करने के लिए कार्य योजना तैयार कर ली गयी है।
- विश्व बैंक द्वारा पोषित उत्तराखण्ड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट के अतिरिक्त वित्त पोषण से विभिन्न जनपदों के 229 सेतुओं के निर्माण के लिये उच्चाधिकार प्राप्त समिति का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

- देहरादून से काशीपुर शहर के मध्य 6 फ्लाई ओवर के निर्माण कार्य प्रगति पर है। एक फ्लाई ओवर का कार्य पूर्ण हो चुका है।
- जनपद टिहरी में डोबरा–चांठी मोटर सेतु लम्बाई 440 मीटर के पुल का कार्य प्रगति पर है, जिसे शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा।
- वित्तीय वर्ष में 748 किमी0 का नवनिर्माण तथा 904 किमी0 लम्बाई के मार्गों का पुनर्निर्माण एवं सुधारीकरण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।
- हरिद्वार शहर में रिंग रोड़ के संरेखण की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।

(43) कृषि क्षेत्रफल में लगातार हो रही कमी के बावजूद नवीनतम तकनीकी एवं वैज्ञानिक प्रयासों व कल्याणकारी योजनाओं से खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

- वित्तीय वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन उन्नीस सौ छः लाख मी० टन रहा, जो कि गत वर्ष की अपेक्षा 1.8 प्रतिशत अधिक है।
- कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा आपसी समन्वय से वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुना करने का लक्ष्य है।
- कृषि उत्पादों के विपणन के लिए नरेन्द्र नगर टिहरी में स्थल निर्माण हेतु कृषि विकास योजना के अन्तर्गत नौ सौ तीस लाख की परियोजना स्वीकृति की गयी है, अतिशीघ्र मण्डी स्थापना की कार्यवाही कर ली जायेगी।
- कृषि विकास योजना के तहत स्थानीय आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार की परम्परागत फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों, जड़ी–बूटी, सगन्ध पौध, रेशम के 3900 क्लस्टर संचालित किए जा रहे हैं।
- राज्य को आर्गेनिक स्टेट बनाने का कार्य क्रमबद्ध रूप से संचालित हो रहा है, 10 विकास खण्डों को पूर्ण जैविक घोषित किया जा चुका है

- प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में बिखरी हुयी जोतें तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों की बहुलता को देखते हुए कलस्टर आधारित कृषि को प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत राज्य सरकार क्लस्टर आधारित एकीकृत कृषि आदर्श ग्राम योजना संचालित कर रही है।

- सुदूरवर्ती क्षेत्रों को कृषि यंत्रीकरण से जोड़ने के उद्देश्य से न्याय पंचायत एवं ग्राम स्तर तक फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए जा रहे हैं। वर्ष के अन्त तक लगभग नौ सौ फार्म मशीनरी बैंक स्थापित कर दिए जाएगें।

- प्रत्येक जनपद में 10 हाई ग्रोथ क्लस्टर बनाए जाएगें, जिसमें कृषि, औद्यानिकी एवं संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा।

- खाद्य प्रसंस्करण एवं विपणन को बढ़ावा दिये जाने हेतु उत्तराखण्ड इन्वेस्टर्स समिट में परम्परागत जैविक प्रोसेसिंग/प्रसंस्करण से संबंधित लघु उद्योग स्थापित करने हेतु 8 निवेशकों द्वारा रूपये तेरह सौ करोड़ का एम०ओ०यू० किया गया है।

- किसान सम्पदा योजना के अन्तर्गत कृषि प्रसंस्करण कलस्टर हेतु आधारिक संरचना का कार्य हेतु प्रस्तावित किया गया है। इस योजना हेतु भारत सरकार द्वारा दस करोड़ का अनुदानित की जायेगी।

(44) मेरी सरकार ने गन्ना फसल का क्षेत्रफल 0.92 लाख हेक्टेयर निर्धारित किया है। जो विगत वर्ष के सापेक्ष आठ प्रतिशत अधिक है। चालू वित्तीय वर्ष में गन्ना क्षेत्रफल 1.00 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य है।

- राज्य की चीनी मिलों द्वारा चार सौ नौ लाख कुन्तल गन्ना पेराई करते हुए कुल बयालीस लाख कुन्तल चीनी का उत्पादन किया है। गन्ना मूल्य आंकलन एक लाख उन्तीस हजार दो सौ उन्तालिस लाख के सापेक्ष तिरानवे हजार दो सौ पचपन लाख का गन्ना मूल्य भुगतान किया जा चुका है।

- विकसित उन्नतशील गन्ना प्रजातियों को प्रदेश की जलवायु एवं मृदा के अनुकूल कृषकों के खेत तक उपलब्ध कराया जा रहा है।
- सहकारी गन्ना विकास समितियों के माध्यम से कृषकों को कृषि निवेशों के रूप में दो हजार छः सौ तिरसठ लाख रूपये नाबार्ड से ऋण वितरित किया गया है।

(45) मेरी सरकार ने किसानो की आय को दो गुना करने के उद्देश्य से दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना का प्रारम्भ कर योजना से पैंसठ हजार कृषक सदस्यों को तीन सौ पचीस करोड़ अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण वितरित किया है। तथा इस योजना के अन्तर्गत ब्याज वहन हेतु तीस करोड का बजट प्राविधान किया गया है।

- प्रदेश में पैक्सो का व्यवसाय बढानें एवं ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को सहकारी समितियों के माध्यम से अधिकाधिक सेवायें उपलब्ध कराने हेतु कृषि ऋण व उर्वरक को बहुद्देशीय समितियों के रुप में परिवर्तित किया गया है।
- रुद्रप्रयाग, चम्पावत एवं बागेश्वर में जिला सहकारी बैंक खोलने की प्रक्रिया गतिमान है।
- प्रदेश की महिलाओं को निःसंकोच बैंकिग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु समस्त जिला सहकारी बैंकों की महिला शाखाओं का सफल संचालन किया जा रहा है।

(46) मेरी सरकार का लक्ष्य जलागम प्रबन्ध योजनाओं प्राकृतिक संसाधनों यथा भूमि, जल एवं वनस्पति का संवर्धन, संरक्षण एवं सुनियोजित प्रबन्धन करना है।

- कृषकों के आय में वृद्धि हेतु कृषि उत्पादों के मूल्य सवंर्धन व वितरण के लिए ग्रोथ सेन्टर की स्थापना की गई है।
- जलागम विकास योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश के 151 सूक्ष्म जलागमों के 4343 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र में परियोजना कार्यक्रमों का कार्यान्वयन गतिमान है।

- संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के वित्त पोषण से जनपद पौड़ी गढवाल में 5.93 मिलियन अमेरिकन डालर लागत की जैफ–6 ग्रीन एग्रीकल्चर परियोजना का कार्यान्वयन किया जाना प्रस्तावित है।

मैने अपनी सरकार के विगत वर्ष में किये गये विकास कार्यो का संक्षिप्त विवरण के साथ–साथ आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की प्राथमिकताओं का संक्षिप्त विवरण आपके समक्ष रखा है। सरकार निष्ठापूर्वक अपने संकल्पों एवं लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सरकार की प्राथमिकता राज्य में विकेन्द्रीकृत विकास तथा सबका साथ, सबका विकास की अवधारणा को लेकर राज्य को विकसित राज्य की श्रेणी में ले जाना है। इस महत्वपूर्ण संकल्प को पूर्ण करने के लिए आपके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी महानुभावों को आगामी वित्तीय वर्ष हेतु वित्तीय व विधायी कार्यों में सक्रिय व सकारात्मक भागीदारी के लिए शुभकामनाएं अर्पित करती हूँ।

धन्यवाद!

– जय हिन्द –